



2026:AHC:65557

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत संख्या- 11444 वर्ष 2026

श्री तेज प्रकाश आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: रिशु भारतीय, शशांक कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 74

माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक वर्मा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री शशांक कुमार और राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री पी. पी. पांडे को सुना।
2. वर्तमान 528 बी.एन.एस.एस. आवेदन आपराधिक पुनरीक्षण संख्या-476 वर्ष 2025 (श्री तेज प्रकाश बनाम श्री जगदीश गोगिया और अन्य) में प्रतिपक्षी संख्या-2 द्वारा दायर एन.आई. अधिनियम की धारा 143-ए के तहत दायर एन.आई. अधिनियम की धारा 143-ए के तहत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-4, आगरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.04.2025 को रद्द करने के लिए दायर किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिपक्षी संख्या-2 ने एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की थी, जिसमें कहा गया था कि आवेदक और प्रतिपक्षी संख्या-2 के बीच पिछले 7-8 वर्षों से व्यावसायिक लेनदेन चल रहा था। शिकायतकर्ता जूते की सामग्री बेचने में लगा हुआ था और आवेदक की मांग पर, प्रतिपक्षी संख्या-2 ने उक्त राशि के भुगतान के लिए 6,44,800/- रुपये के जूते वितरित किए, आवेदक ने शिकायतकर्ता को कुछ सेक्युरिटी चेक दिए थे। शिकायत में कहा गया है कि आवेदक पर शिकायतकर्ता की कुल देय राशि 16,37,782/- रुपये थी, जिसमें से आवेदक द्वारा 1,71,834/- रुपये वापस कर दिए गए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



थे। शेष राशि के लिए आवेदक ने शिकायतकर्ता को कुछ चेक दिए थे और उसे बैंक के समक्ष रखा गया था, जिसे "अपर्याप्त राशि" टिप्पणी के साथ अस्वीकार कर दिया गया था। चेक के अनादर के संबंध में पंजीकृत नोटिस जारी किया गया था, लेकिन आवेदक ने राशि वापस नहीं की तो तत्काल शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत के लंबित रहने के दौरान, शिकायतकर्ता ने विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष अंतरिम मुआवजे के लिए धारा 143-ए के तहत आवेदन किया और विद्वान मजिस्ट्रेट ने 143-ए आवेदन की अनुमति दी। आवेदक ने 143-ए आवेदन के खिलाफ विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष आपति दर्ज कराई, लेकिन विद्वान मजिस्ट्रेट ने आवेदक की आपति पर विचार नहीं किया है और आवेदक को अंतरिम मुआवजे के रूप में प्रतिपक्षी संख्या-2 को कुल शेष राशि का 20% भुगतान करने का निर्देश दिया है, जो कि 66.800/- रुपये आता है।

4. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि दिनांक 07.04.2025 के आदेश से व्यथित होकर, प्रतिपक्षी संख्या-2 को अंतरिम मुआवजे की अनुमति देते हुए, आवेदक ने विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश, आगरा के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण संख्या-478 वर्ष 2025 के साथ पुनरीक्षण दायर किया, लेकिन इसे दिनांक 13.01.2026 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 07.04.2025 का आदेश, जिसमें एन.आई. अधिनियम की धारा 143-ए के तहत आवेदन की अनुमति दी गई थी, अवैध और मनमाना है साथ ही पुनरीक्षण न्यायालय ने भी दिनांक 13.01.2026 का आदेश पारित किया है, जो न्यायिक दिमाग के अनुप्रयोग के बिना है और इसे रद्द करने योग्य है। आवेदक ने विचारण न्यायालय के समक्ष आपति दर्ज की थी, लेकिन विचारण न्यायालय ने आपति पर विचार नहीं किया और केवल अंतरिम भरण-पोषण के लिए प्रतिपक्षी संख्या-2 की प्रार्थना पर विचार किया और प्रतिपक्षी संख्या-2 के आवेदन 143-ए की अनुमति दी। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने राकेश रंजन श्रीवास्तव बनाम झारखंड राज्य और एक अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया है, 15.03.2024 को पारित आपराधिक अपील संख्या-741 वर्ष 2024 में, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एन.आई. अधिनियम की धारा 143-ए के तहत आवेदन पर विचार



करने के लिए कुछ पैरामीटर तैयार किए हैं। प्रासंगिक प्रस्तर-19 में नीचे उद्धृत किया गया है:-

"19. जो पहले अवधारित किया गया है, उसके अधीन, मुख्य निष्कर्षों को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

a. धारा 143A की उप-धारा (1) के तहत शक्ति का प्रयोग विवेकाधीन है। प्रावधान निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है। प्रावधान में प्रयुक्त शब्द "हो सकता है" को "करेगा" के रूप में नहीं समझा जा सकता है। धारा 143A के तहत की गई प्रार्थना पर निर्णय लेते समय, न्यायालय को सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने वाले संक्षिप्त कारणों को दर्ज करना चाहिए।

ग. धारा 143A के तहत विवेक का प्रयोग करने के लिए व्यापक पैरामीटर इस प्रकार हैं:

i. न्यायालय को प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मामले के गुण-दोष और आवेदन के उत्तर में अभियुक्त द्वारा दलील दिए गए बचाव पक्ष के गुण-दोष का मूल्यांकन करना होगा। अभियुक्त की वित्तीय परेशानी पर भी विचार किया जा सकता है।

ii. अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश केवल तभी जारी किया जा सकता है, जब शिकायतकर्ता प्रथम दृष्टया मामला बनाता है।

iii. यदि अभियुक्त का बचाव प्रथम दृष्टया बोधगम्य पाया जाता है, तो न्यायालय अंतरिम मुआवजा देने से इनकार करने में विवेक का प्रयोग कर सकता है।

iv. यदि न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि अंतरिम मुआवजा देने के लिए कोई मामला बनाया गया है, तो उसे दिए जाने वाले अंतरिम मुआवजे की मात्रा पर भी अपना विचार लगाना होगा। ऐसा करते समय, न्यायालय को कई कारकों पर विचार करना होगा जैसे लेन-देन की प्रकृति, यदि कोई हो, आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच संबंध, आदि। किसी दिए



गए मामले के अजीबोगरीब तथ्यों में कई अन्य प्रासंगिक कारक हो सकते हैं, जिन्हें विस्तृत रूप से नहीं कहा जा सकता है। ऊपर बताए गए पैरामीटर संपूर्ण नहीं हैं।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय (ऊपर) द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश अवैध है और इसे रद्द किया जा सकता है।
6. तत्स्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए सबमिशन का विरोध किया।
7. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क को ध्यान में रखते हुए, सबसे पहले आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाया गया निवेदन उन तथ्यों का विवादित प्रश्न है जिनकी इस स्तर पर जांच नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, दिनांक 07.04.2025 के आदेश के अवलोकन पर, जिसके द्वारा प्रतिपक्षी संख्या-2 के आवेदन को आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी, जिससे पता चलता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने आवेदक की आपत्ति पर विचार किया है। विचारण न्यायालय ने पाया है कि आवेदक के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं और आवेदक ने दोषी नहीं ठहराया है और मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने वर्तमान कार्यवाही के तहत प्रथम दृष्टया, अपराध पाया है। विचारण न्यायालय को अंतरिम मुआवजे के लिए महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। विद्वान मजिस्ट्रेट ने एन.आई. अधिनियम की धारा 143-ए के तहत प्रदान किए गए प्रावधान को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्षी संख्या-2 के आवेदन की अनुमति दी है। आवेदक की आपत्ति के अवलोकन पर, जिसमें यह कहा गया है कि उनके द्वारा चेक जारी नहीं किया गया है और उस पर कोई हस्ताक्षर नहीं है और उसने प्रतिपक्षी संख्या-2 को सभी राशि का भुगतान कर दिया है, आवेदक द्वारा उठाई गई आपत्ति तथ्य के विवादित प्रश्न हैं। जिसकी जांच विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमे के चरण में की जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 143A के तहत आवेदन पर विचार करने के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं और आदेश के अवलोकन पर ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने पक्षों के बीच संबंधों और प्रतिपक्षी संख्या-2 को अंतरिम मुआवजे की आवश्यकता पर विचार करने के बाद एन.आई. अधिनियम की धारा 143A के तहत आवेदन की अनुमति दी है। इस न्यायालय को लगता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा



पारित आदेश के साथ-साथ पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मापदंडों और दिशानिर्देशों में हैं। इसके अलावा, धारा 143A स्वयं शिकायतकर्ता/प्रतिपक्षी संख्या-2 को अंतरिम मुआवजा प्रदान करती है और यह भी प्रदान करती है कि यदि आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा बरी हो जाता है तो शिकायतकर्ता से राशि वापस की जा सकती है। आपराधिक पुनरीक्षण संख्या-476 वर्ष 2025 में एन.आई. अधिनियम की धारा 143-ए के तहत आवेदन पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-25, आगरा द्वारा दिनांक 13.01.2026 को पारित आदेश और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-4, आगरा द्वारा शिकायत मामले संख्या-22955 वर्ष 2023 में दिनांक 07.04.2025 को पारित आदेश न्यायसंगत और उचित है। किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. श्री ओम सेल्स बनाम अभय कुमार @ अभय पटेल और 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 2897 में रिपोर्ट किए गए अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णयों पर विचार किया है:

"14. मारुति उद्योग लिमिटेड बनाम नरेंद्र और अन्य में, इस न्यायालय ने माना कि एक अनुमान लगाया जाना चाहिए कि चेक के धारक को किसी भी ऋण या अन्य दायित्व के निर्वहन के लिए धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त हुआ है, जब तक कि ततस्य विपरीत साबित न हो जाए और इसलिए, उच्च न्यायालय कार्यवाही के प्रारंभिक चरण में अभियुक्त की याचिका पर विचार करने और उसे स्वीकार करने और शिकायत को रद्द करने में उचित नहीं था।

15. इसी तरह, रंगप्पा बनाम श्री मोहन में, यह माना गया था कि एन.आई. अधिनियम की धारा 139 द्वारा अनिवार्य अनुमान में कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता का अस्तित्व शामिल है। यह देखा गया कि इस तरह की धारणा खंडन योग्य है, और अभियुक्त को मुकदमे में अपना बचाव करना चाहिए।

16. राजेशभाई मुलजीभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य में, यह माना गया था कि उच्च न्यायालय को ऋण या देयता के निर्वहन के लिए जारी किए जा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रहे चेक के संबंध में तथ्य के विवादित प्रश्नों में जाकर एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत आपराधिक शिकायत को रद्द नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, जब एन.आई. अधिनियम की धारा 139 ऋण या देयता के निर्वहन के लिए जारी किए जा रहे चेक के संबंध में एक वैधानिक धारणा उठाती है।

9. रतीश बाबू उन्नीकृष्णन बनाम राज्य (दिल्ली का एन.सी.टी.) में, इस न्यायालय ने माना कि जब एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत कोई कानूनी धारणा होती है, तो शिकायत को रद्द करने के लिए पूर्व-परीक्षण चरण में तथ्य के विवादित प्रश्न पर विस्तृत जांच करना विवेकपूर्ण नहीं होगा। निर्णय में प्रासंगिक टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

"17. जैसा कि ऊपर निर्धारित कानून का प्रस्ताव यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि अदालत को पूर्व-परीक्षण चरण में शिकायत को रद्द करने की राहत देने में धीमा होना चाहिए, जब तथ्यात्मक विवाद विशेष रूप से कानूनी अनुमान के कारण संभावना के दायरे में हो, जैसा कि इस मामले में है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी भी सबूत को जोड़ने के बिना तथ्यात्मक बचाव को एक अभेद्य गुणवत्ता की आवश्यकता है, ताकि शिकायत में लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया जा सके।

18. पूर्व-परीक्षण चरण में आपराधिक प्रक्रिया को बाधित करने के परिणाम गंभीर और अपूरणीय हो सकते हैं। प्रारंभिक चरणों में कार्यवाही को रद्द करने के परिणामस्वरूप पक्षों को सबूत पेश करने का अवसर नहीं मिलेगा और इसका परिणाम यह होगा कि उचित मंच यानी विचारण न्यायालय को भौतिक साक्ष्य का वजन करने से बाहर कर दिया जाता है। यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो अभियुक्त को आपराधिक प्रक्रिया में अनुचित लाभ दिया जा सकता है। इसके अलावा, कानूनी अनुमान के कारण, जब अपीलकर्ता द्वारा चेक और हस्ताक्षर पर विवाद नहीं किया जाता है, तो इस स्तर पर सुविधा का संतुलन शिकायतकर्ता/अभियोजन पक्ष के पक्ष में होता है, क्योंकि अभियुक्त को अनुमान का खंडन करने के लिए मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष में साक्ष्य पेश करने का अवसर मिलेगा।



19. इस प्रकार, शिकायतकर्ता को गैर-सूट करने के लिए, सम्मन आदेश के चरण में, जब तथ्यात्मक विवाद को अभी तक प्रचारित नहीं किया गया है और विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है, हमारी राय में विवेकपूर्ण नहीं होगा। प्रथम दृष्टया धारणा के आधार पर, विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारण के अधीन यहां आपराधिकता के एक तत्व को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। इसलिए, जब कार्यवाही एक प्रारंभिक चरण में होती है, तो आपराधिक प्रक्रिया को रद्द करने के योग्य नहीं है।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त मामले का निर्णय करते समय, प्रस्तर-13 और 18 में कहा है कि:

"13. हालांकि, उच्च न्यायालय ने धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में, यह परीक्षण करने के लिए आगे बढ़े कि क्या चेक किसी भी ऋण या अन्य देयता के पूरे या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए जारी किया गया था। हमारे विचार में, इस तरह की कवायद अनुचित थी क्योंकि, एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत, एक धारणा है कि चेक के धारक को किसी भी ऋण या अन्य देयता के निर्वहन के लिए, पूरी तरह या आंशिक रूप से, धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त हुआ था। इस अनुमान का खंडन मुकदमे में किए गए सबूतों द्वारा किया जा सकता है। एक फोर्टियोरी, उक्त मुद्दे को उचित रूप से या तो मुकदमे में, या बाद में, मुकदमे के समापन पर, अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तय किया जा सकता है।

"18. इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों के साथ-साथ एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने ऋण या देयता के निर्वहन के लिए जारी किए जा रहे चेक के संबंध में, पूर्व-परीक्षण चरण में एक रोविंग जांच करके एक त्रुटि की है। हमारे विचार में, इस तरह की कवायद संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के योग्य नहीं थी, खासकर जब शिकायत के आरोपों



से पता चला कि चेक दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था।
चूंकि धारा 138 एन.आई. अधिनियम के आवश्यक अवयवों की पूर्ति प्रथम
दृष्टया शिकायत के आरोपों से बनाई गई है, इसलिए हमारे विचार में, न तो
समन आदेश और न ही शिकायत को उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व-परीक्षण
चरण में रद्द किया जा सकता था।

11. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा किसी भी
हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, प्रस्तुत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

मार्च 30, 2026

नितिन वर्मा

(न्यायमूर्ति दीपक वर्मा)